योजना एवं विकास विभाग को बनाया गया नोडल विभाग

विकसित भारत 2047 की तर्ज पर विकसित बिहार बनाने की तैयारी

एक्सक्लूसिव

कैलाशपति मिश्र, पटना

विकसित भारत 2047 की तर्ज पर बिहार को 2047 तक एक विकसित राज्य बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने की तैयारी शुरू हो गयी है.इस डॉक्यूमेंट में बिहार के भविष्य की योजनाओं का खाका होगा.इसके लिए योजना एवं विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है.योजना एवं विकास विभाग ने इसके लिए काम शुरू कर दिया है.सभी विभागों से इसके लिए योजना की मांग की गयी है.यह डॉक्यूमेंट अगले 20 साल के लिए राज्य के विकास का रोडमैप होगा.नीति आयोग ने भी बिहार से भविष्य की योजनाओं का खाका मांगा है ताकि विकसित भारत 2047 की योजनाओं भी बिहार पर फोकस किया जा सके.

हर विभाग के विजन को किया जायेगा शामिल

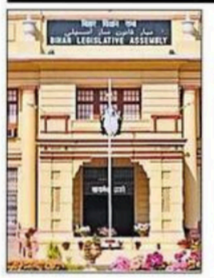

इस डॉक्यूमेंट में हर विभाग के विजन को शामिल किया जायेगा .बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए क्या-क्या करना होगा, इसकी पूरी योजना होगी. साथ ही, ये भी बताया जायेगा कि बिहार अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा .यह दस्तावेज अगले दो दशकों के लिए बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करेगा .साथ ही सतत विकास के लक्ष्यों के साथ समन्वित रहेगा.

प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप रखेगा नजर

इस डॉक्यूमेंट में राज्य के विकास की गति को और तेज करने के साथ-साथ उसे बरकरार रखने की योजना भी होगी .राज्य,अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कैसे करे, इसकी योजना भी इस डॉक्यूमेंट में होगी .सरकार राज्य में चल रही योजनाओं की निगरानी के लिए राज्य परिवर्तन संस्थान बनायेगी .50 करोड़ रुपये से ज्यादा की योजनाओं पर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप (पीएमजी) की तर्ज पर नजर रखी जायेगी .इसके लिए एक तकनीकी पोर्टल भी बनाया जायेगा. इसकी शुरुआत के लिए एक विशेष टीम भी बनायी जा रही है .

कॉलेजों के संबंधन के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी नहीं हुई शुरू

पटना. बिहार के परंपरागत विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के स्थायी संबंधन की प्रक्रिया रुकी हुई है. संबंधन अगले शैक्षणिक सत्र 2025-29 के लिए दिये जाने हैं. दरअसल संबंधन की यह समूची कवायद एनआइसी की वेबसाइट से की जाती थी.

ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू कराने के लिए बेंगलुरु की कंपनी से होगा अनुबंध: एनआइसी ने हाथ उठा दिये हैं. लिहाजा शिक्षा विभाग, कॉलेजों के संबंधन की ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू कराने के लिए बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी से अनुबंध करने जा रही है. विभाग इस बारे में जल्दी ही आधिकारिक निर्णय लेने जा रहा है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार संबंधन की प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल शिक्षा विभाग पहले ही जारी कर चुका है. इस ऑनलाइन शेड्यूल में संबंधन की कवायद सितंबर से ऑनलाइन विभागीय पोर्टल पर होनी थी.

हालांकि, कुछ तकनीकी कारणों से यह प्रक्रिया रुक गयी. यह व्यवधान अभी तक बना हुआ है. विभागीय जानकारों के अनुसार छठ बाद विभाग वेबसाइट को ओपन करने जा रहा है, ताकि नये कॉलेज संबंधन पाने के लिए आवेदन द सकें. बता दें कि बिहार में कॉलेजों के संबंधन की प्रक्रिया पिछले दो साल से ऑनलाइन है.

यूनिसेफ और यूएनइएसकैप के साथ सरकार ने की साझेदारी

पटना. बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीइएस) ने राज्य में सिविल पंजीकरण और महत्वपूर्ण सांख्यिकी (सीआरवीएस) प्रणाली को 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण की दिशा में सुदृढ़ बनाने के लिए यूनिसेफ और एवं संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनएसकैप) के साथ साझेदारी की है. इसके चलते यूएनइएसकैप के वरिष्ठ सलाहकार राज गौतम मित्रा, यूनिसेफ की एसपीएसपी विशेषज्ञ डा उर्वशी कौशिक, यूनिसेफ बिहार के एसपीएसपी विशेषज्ञ डॉ अभय कुमार और यूएनइएसकैप बिहार के सलाहकार डॉ जयंत कुमार बसु की टीम ने बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार से मुलाकात की. इस बैठक का उद्देश्य राज्य में सीआरवीएस प्रणाली के सुधार के लिए बीपीआइ मॉडल पर एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करने पर चर्चा करना था. सेंथिल और उनकी टीम जिसमें डीइएस के संयुक्त निदेशक शैलेंद्र कुमार पांडे और उपनिदेशक प्रवीन कुमार शामिल रहे, ने सीआरवीएस सुदृढ़ीकरण परियोजना को लागू करने में बिहार सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता जतायी.

यूनिसेफ बिहार, डीइएस को मौजूदा सीआरवीएस प्रणाली और उसकी प्रक्रियाओं की चुनौतियों का आकलन करने में तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है. इसके तहत व्यापक हस्तक्षेप किये जायेंगे जिनमें पंजीकरण अधिकारियों और सूचना देने वालों का क्षमतावर्धन, जागरूकता और संचार सामग्री, छूटे हुए पंजीकरणों को पूरा करने के लिए कैच अभियान, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, और आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण (एएलबीआर) का कार्यान्वयन शामिल है. इसी प्रकार की तकनीकी सहायता झारखंड सरकार को भी यूनिसेफ इंडिया और यूएनएसकैप द्वारा प्रदान की जा रही है.

रुमेटोलॉजिकल डिजीज: समय पर पहचान से आसान इलाज

डॉ. किरण सेठ, फेलिक्स अस्पताल, भारतीय रूमेटोलॉजी एसोसिएशन (IRA) हेड, दिल्ली-एनसीआर

रुमेटोलॉजिकल डिजीज क्या है?

रुमेटोलॉजिकल डिजीज ऑटोइम्यून रोगों का समूह है, जिसमें शरीर की इम्यूनिटी स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है। इसके कारण जोड़ों में सूजन और दर्द होता है, जिससे दैनिक जीवन में कठिनाई होती है।

लक्षण:

- सुबह उठने पर शरीर में अकड़न
- थकान, मांसपेशियों में खिंचाव
- हल्का बुखार (99-100°F), कमर दर्द
- जोड़ों में सूजन, आंखों में लाली
- सर्दियों में उंगलियों का रंग बदलना

प्रमुख रोग:

- गठिया (Arthritis)
- ल्यूपस (Lupus)
- स्पोंडिलाइटिस

रोग का असर:

इन रोगों से फेफड़ों, दिल और किडनी पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जिससे डिसेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं, जिससे उनके परिवार पर भी असर होता है।

जांच और उपचार:

रुमेटोलॉजिकल डिजीज का इलाज जल्द शुरू करने से अपंगता और अंगों के विफल होने का खतरा कम हो सकता है।

जांच: ब्लड टेस्ट, एक्स-रे

उपचार: DMARDs (डिजीज मॉडिफाइड एंटी-रूमेटिक ड्रग्स), NSAIDs, लो-डोज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स

कारण:

- वजन अधिक होना, रात में जागना
- प्रॉपर डाइट का अभाव
- धूम्रपान और शराब का सेवन

जागरूकता और रोकथाम के लिए अभियान:

भारतीय रूमेटोलॉजी एसोसिएशन (IRA) ने अप्रैल को रुमेटोलॉजिकल डिजीज जागरूकता माह घोषित किया है, जिसमें लोगों को बीमारी के लक्षण, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और उपचार की जानकारी दी जाएगी।

महत्वपूर्ण संदेश:

समय पर पहचान और सही इलाज से इन रोगों का प्रभावी नियंत्रण संभव है।

दूसरे जिले में नहीं हो सकेगा राजस्व कर्मियों का तबादला

पटना. राज्य में राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण किसी दूसरे जिले में नहीं हो सकेगा. ये जिस जिले में काम कर रहे हैं, उसी जिले के किसी अंचल में उनका स्थानांतरण किया जा सकेगा. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नियमों का हवाला देते हुये अन्य जिले में तबादला करने के लिए प्राप्त आवेदनों को अमान्य कर दिया है. साथ ही इस आदेश का पत्र सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, सभी संबंधित समाहर्ता, अपर समाहर्ता और अंचल अधिकारियों को भेज दिया है. विभागीय आदेश में हाल ही में नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों से प्राप्त ऐसे 11 आवेदनकर्ताओं का उल्लेख किया गया है. इन नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों

विक्रमशिला से कटारिया के बीच गंगा नदी पर बनने वाले रेल पुल के लिए टेंडर जारी

संवाददाता,पटना

योजना

भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला से कटारिया के बीच बनने वाले नये रेल पुल का रास्ता साफ हो गया है. रेलवे ने इस नये पुल के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है. पाच दिसंबर को टेंडर खोला जायेगा. करीब पांच सौ करोड़ से अधिक रुपये के इसीआर द्वारा जारी इस टेंडर में नदी पार्ट में दो लाइन का पुल स्ट्रक्चर और सिंगल होगा. केंद्र सरकार ने इसी साल नौ अगस्त को भागलपुर में गगा नदी पर विक्रमशिला से कटारिया के बीच नयी रेल लाइन के निर्माण की मंजूरी दी है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2549 करोड़ रुपये खर्च होंगे. परियोजना को 2030-31 में पूरा करने का लक्ष्य है. इसके पूरे हो जाने से झारखंड से बिहार आना-जाना की तरफ से बटेश्वर स्थान गंगा नदी के दूसरे ओर नवगछिया के कटारिया तक नयी रेल लाइन बिछायी जायेगी. इससे गंगा के दोनों किनारे जुड़ जायेंगे. बिहार के सीमांचल के जिले कटिार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया को इसे बहुत लाभ होगा. विक्रमशिला स्टेशन भागलपुर -साहिबगंज लाइन पर और कटारिया स्टेशन कटिहार-बरौनी रेल लाइन पर स्थित है. इसके